विविध नागरिक

आर. एस. नरूला न्यायमूर्ति के समक्ष

वाटू राम, - *याचिकाकर्ता, बनाम।*

हरियाणा राज्य *आदि, - उत्तरदाता।*

1970 का सी. डब्ल्यू. नंबर 2370।

7 जनवरी, 1971।

*पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (*1953 का IV) - धारा *10, 15* और *102 - जांच लंबित होने तक पंचायत के सरपंच का निलंबन - ऐसी पंचायत - क्या निलंबन अवधि के दौरान सरपंच के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अपने पंचों में से एक का चुनाव नहीं कर सकती है* - धारा *102* (1) - *क्या* अंतर्अधिकार *- एक सरपंच के खिलाफ विभागीय जांच - क्या अदालत में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मुकदमा चलाया जा सकता है।*

यह माना गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 15 संबंधित पंचायत के किसी भी मौजूदा पंच को सरपंच के रूप में निर्वाचित करने के लिए अधिकृत करती है, जो मूल सरपंच की अनुपस्थिति के दौरान उस कार्यालय के विशिष्ट कार्यों को पूरा कर सकता है, जिसे जांच के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 15 सरपंच की अनुपस्थिति के दौरान की जा सकने वाली व्यवस्थाओं से संबंधित सामान्य प्रावधान है। आम तौर पर प्रावधान अस्थायी और साथ ही आकस्मिक प्रकृति की स्थायी रिक्तियों को कवर करता, लेकिन धारा 10 को आकस्मिक प्रकृति की रिक्तियों के मामलों को कवर करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में लागू किया गया है जो इस अर्थ में स्थायी हैं कि सीट खाली करने वाला सरपंच संभवतः अपने कार्यालय के शेष कार्यकाल के दौरान इसमें वापस नहीं आ सकता है। धारा 15 अन्य सभी मामलों पर लागू होती है। जबकि एक नए सरपंच को धारा 10 के तहत चुना जाना है, एक मौजूदा पंच को अकेले एक सरपंच के निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है जो धारा 15 के तहत अनुपस्थित है। फिर, धारा 10 के तहत एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सरपंच मूल सरपंच के शेष कार्यकाल के दौरान पद पर रहता है, लेकिन धारा 15 के तहत सरपंच के निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चुना गया पंच केवल तब तक काम करता है जब तक कि मूल सरपंच वापस नहीं आ जाता या अपना कार्यालय खाली नहीं कर देता और धारा 10 के तहत एक नव निर्वाचित सरपंच द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नव निर्वाचित सरपंच के पास सरपंच की सभी शक्तियां हैं, लेकिन धारा 15 के तहत

निर्वाचित एक व्यक्ति केवल उस प्रावधान में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इसलिए, दो खंड विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए हैं। (पैरा 6)।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 102 (1) *अंतर्विहित है।*

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 102 (2) के तहत सरपंच के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी जांच के दौरान धारा 102 की उप-धारा (1) के तहत उसे निलंबित करने पर कोई रोक नहीं है, *भले ही उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सक्षम अदालत में लंबित हो। (पैरा 4) ।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि 10 जुलाई 1970 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए सर्टिओरारी, मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे आगे कोई कार्रवाई न करें और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता से प्रभार लेने पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आर. एन. नरूला ।

उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता आरएन मित्तल।

निर्णय।

आर. एस. नरूला, न्यायमूर्ति - 1.यह दावा करने के अलावा कि उपायुक्त, करनाल, प्रतिवादी संख्या 2, का 10 जुलाई, 1970 का आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम संख्या 4) की धारा 102 की उप-धारा (1) के तहत ग्राम पंचायत, कांगथली, ब्लॉक गुला, जिला करनाल के सरपंच के कार्यालय से निलंबित कर दिया गया था, अवैध और अमान्य चूंकि याचिकाकर्ता को पहले उन्हीं आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, जिनमें अब जांच की मांग की गई है, याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन के उपरोक्त आदेश को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में दो नई दलीलें उठाई हैं। ये तर्क हैं (i) अधिनियम की धारा 102 (1) अधिकारहीन *और अमान्य* है, और (ii) भले ही जांच लंबित होने तक सरपंच को निलंबित करने की वैध शक्ति अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की गई मानी जाती है, फिर भी अधिनियम के तहत विधिवत निर्वाचित सरपंच के निलंबन की अवधि के दौरान सरपंच के कार्यों का निर्वहन

करने के लिए किसी अन्य को नियुक्त करने के लिए किसी भी प्राधिकरण में अधिनियम द्वारा कोई शक्ति निहित नहीं है। ऊपर उल्लिखित तीन प्रश्न यहां विस्तृत परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं।

2. 1963-64 में हुए पंचायत चुनावों में, याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत जो की प्रश्नाधीन है के सरपंच के रूप में चुना गया था। 26 मार्च, 1968 को निलंबन का आदेश (अनुलग्नक 'डी'), जिसमें उन आरोपों को शामिल किया गया था, जिन पर निलंबन का निर्देश दिया गया था, याचिकाकर्ता को दिया गया था और उन्हें वास्तव में उन आरोपों पर निलंबित कर दिया गया था। 27 मई, 1970 के आदेश अनुलग्नक 'ए' द्वारा, उन्हें बहाल कर दिया गया था। 10 जून, 1970 को उन्हें खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा सरपंच के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए कहा गया। 2 जुलाई, 1970 को याचिकाकर्ता को एक नया आरोप पत्र (कॉपी अनुलग्नक 'बी') दिया गया, जो 26 मार्च, 1968 के आरोप-पत्र की लगभग शब्दशः प्रति थी, (अनुलग्नक 'डी'), लगभग 8 दिन बाद, 10 जुलाई, 1970 को निलंबन का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'सी') याचिकाकर्ता को दिया गया था। आदेश की प्रति खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, घुला को अग्रेषित किए जाने के समर्थन में यह निर्देश दिया गया था कि उक्त अधिकारी याचिकाकर्ता से सरपंच के कार्यालय का प्रभार विधिवत स्थानांतरित करवाएं।

3. 28 जुलाई, 1970 को यह रिट याचिका ऊपर उल्लिखित कानूनी आधार पर,10 जुलाई, 1970 के निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी और आगे इस आधार पर कि उक्त आदेश हरियाणा राज्य सरकार की नीति के अनुसरण में दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया था ताकि सभी पंजाबी भाषी व्यक्तियों (पंजाबी हिंदुओं और सिखों) को करनाल जिले और विशेष रूप से घुला तहसील से बाहर कर दिया गया हो। याचिका के साथ 26 मार्च, 1968 के पहले आरोप-पत्र की कोई प्रति दायर नहीं की गई थी। इसलिए, जब यह मामला 29 जुलाई, 1970 को मोशन बेंच (हरबंस सिंह मुख्यन्यमूर्ति और पीसी जैन न्यायमूर्ति) के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ता के वकील ने उस आरोप-पत्र की एक प्रति पेश करने के लिए समय मांगा, ताकि उनके द्वारा आग्रह किए गए पहले कानूनी बिंदु को साबित किया जा सके। स्थगित सुनवाई पर, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक 'डी' दायर किया और कहा कि उन्हें 1968 में निलंबित कर दिया गया था और दो साल बाद बहाल कर दिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें उसी आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इसलिए, प्रस्ताव पीठ ने प्रतिवादियों को 27 अगस्त, 1970 तक वापसी के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस के जवाब में, दूसरे प्रतिवादी ने 27 अगस्त, 1970 को स्थगित प्रस्ताव की सुनवाई में 25 अगस्त, 1970 को अपना हलफनामा दायर किया। हलफनामे के

पैराग्राफ 2 में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश तकनीकी खामी के कारण 27 मई, 1970 को वापस ले लिया गया था और याचिकाकर्ता को तदनुसार बहाल कर दिया गया था और जहां तक निलंबन और आरोप-पत्र का आदेश मूल रूप से 26 मार्च के उसी आदेश में सन्निहित किया गया था। 1968 में, याचिकाकर्ता की बहाली के आदेश के पारित होने के साथ आरोप-पत्र भी समाप्त हो गया। यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता को 2 जुलाई, 1970 को एक नया आरोप पत्र जारी किया गया था, और उसके बाद 10 जुलाई, 1970 को उन्हें उपरोक्त परिस्थितियों में उनके खिलाफ जांच लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया गया था। चूंकि लिखित बयान में पहले की कार्यवाही में कथित तकनीकी खामी का कोई अंदाजा नहीं दिया गया था, इसलिए उस दिन प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता ने 27 अगस्त, 1970 को मोशन बेंच से स्थगन के लिए अनुरोध किया ताकि वह लिखित बयान को विस्तृत कर सकें।स्थगित सुनवाई पर, यानी 10 सितंबर, 1970 को, करनाल के उपायुक्त ने 9 सितंबर, 1970 को एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ पिछली कार्यवाही का विवरण दिया। उन विवरणों के बावजूद, प्रतिवादियों ने यह स्वीकार नहीं किया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच की गई थी या कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था या याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने वाली कोई रिपोर्ट बनाई गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता ने 26 मार्च, 1968 से 27 मई, 1970 की अवधि के दौरान की गई जांच के बारे में विवरण देने के लिए समय मांगा। अगली स्थगित प्रस्ताव सुनवाई में, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से और हलफनामे दायर किए। याचिकाकर्ता के 21 सितंबर, 1970 के हलफनामे के पैराग्राफ 1 से 5 में, उन्होंने उन्हें प्राप्त नोटिस का विवरण, उनके द्वारा पेश किए गए हलफनामों के माध्यम से सबूत, जांच अधिकारी की रिपोर्ट का विवरण दिया, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया और उसके खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने की सिफारिश की और उस आधार पर दावा किया कि उपायुक्त के हलफनामे में दिए गए बयान सही नहीं थे। प्रतिवादियों की ओर से, उपायुक्त ने खुद महसूस किया कि उनके पहले के हलफनामे स्पष्ट नहीं थे और इसलिए, 20 सितंबर, 1970 को एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता से निलंबन के अपने पहले के आदेश के कानूनी नहीं होने के बारे में आवेदन प्राप्त करने पर मामले को उपायुक्त द्वारा खंड विकास और पंचायत अधिकारी घुला को भेज दिया गया था उनकी टिप्पणियों के लिए, जिन्होंने याचिकाकर्ता के आवेदन पर अपनी टिप्पणी भेजने के बजाय, इसे सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी को टिप्पणियों के लिए भेजा था, जिन्होंने बदले में, याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष पेश किए गए कुछ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए कुछ हलफनामे

भी प्राप्त किए। यह अभी भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। यह कहा गया कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले की जांच के बाद यह पता चला कि याचिकाकर्ता के निलंबन का प्रारंभिक आदेश तत्कालीन उपायुक्त द्वारा उस समय पारित किया गया था जब उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं थी और इस प्रकार याचिकाकर्ता के निलंबन के आदेश कानून के अनुसार नहीं थे और, इसलिए, याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया गया और उसके निलंबन का एक नया आदेश पारित किया गया। यह जोड़ा गया कि सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए किसी भी सबूत या उनके द्वारा दिए गए किसी भी निष्कर्ष को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के अनुसरण में जांच के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है और सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी की टिप्पणियां याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में पेश किए गए सबूतों पर आधारित थीं नाकी याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोपों के संबंध में. यह उपर्युक्त परिस्थितियों में था कि रिट याचिका को 21 सितंबर, 1970 को मोशन बेंच द्वारा स्वीकार किया गया था, क्योंकि बेंच ने महसूस किया कि पूरे मामले को देखने की आवश्यकता है। याचिका स्वीकार किए जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से कोई और हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

4. प्रतिवादी की ओर से वकील आर. एन. मित्तल ने करनाल के उपायुक्त कार्यालय और पंचायत समिति, घुला से संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय के पूरे मूल रिकॉर्ड पेश किए। मूल रिकॉर्ड ज्यादातर हिंदी में हैं और दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने उन्हें मुझे पढ़ा। उन रिकॉर्डों से पता चलता है कि 19 सितंबर, 1968 को अपना अभ्यावेदन दायर करने के बाद, (20 सितंबर, 1970 को उपायुक्त के हलफनामे के साथ संलग्न अनुलग्नक आर-2) अनावश्यक उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा से बचने के लिए मामले की गहन जांच का दावा करते हुए, याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी, 1969 को हरियाणा के पंचायत निदेशक और उपायुक्त करनाल को आवेदन (अनुलग्नक 'आर-4' और 'आर-5' की प्रतियां) भेजे कि इस न्यायालय के हाल के निर्णय के मद्देनजर उनका निलंबन अमान्य होने के कारण उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। इस बीच, हरियाणा के पंचायत निदेशक ने 1 जनवरी, 1969 को करनाल के उपायुक्त को पत्र लिखकर *सूचित* करने के लिए कहा था कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ 26 मार्च, 1968 को याचिकाकर्ता को निलंबित करने से पहले पंचायत निदेशक या सरकार द्वारा किसी जांच का आदेश दिया गया था। जाहिर है, इस पत्र को इस न्यायालय की इस आशय की घोषणाओं के कारण संबोधित किया गया था कि एक सरपंच को निलंबित करने के लिए अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत एक

आदेश सरकार द्वारा आदेशित जांच के दौरान पारित नहीं किया जा सकता है। मूल रिकॉर्ड से पता चला है कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए हलफनामों और सबूतों के आधार पर 12 अगस्त, 1969 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने का सुझाव दिया गया था और याचिकाकर्ता की बहाली की भी सिफारिश की गई थी। खंड विकास और पंचायत अधिकारी की उस रिपोर्ट को अपनाने की सिफारिश उप-विभागीय अधिकारी ने 26 नवंबर, 1969 के अपने नोट में की थी। जब 1 दिसंबर, 1969 को उस नोट को उपायुक्त के समक्ष रखा गया, तो उन्होंने उस पर लिखा कि उन्हें लगा कि मामले की आगे की जांच आवश्यक है और इसलिए, मामले को उनके उत्तराधिकारी के सामने रखने का निर्देश दिया, संभवतः क्योंकि तत्कालीन उपायुक्त स्थानांतरण के आदेशों के अधीन थे। इसके बाद मामले को जिला अटॉर्नी (डीए) के पास भेज दिया गया। 20 जनवरी, 1970 को जिला अटॉर्नी ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच का कोई आदेश सरकार द्वारा कभी पारित नहीं किया गया था और इसलिए, उसके निलंबन का आदेश कानूनी नहीं था और परिणामस्वरूप उसे बहाल करना और फिर जांच का आदेश देना और उस उद्देश्य के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करना उचित होगा। उन्होंने उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर यह राय व्यक्त की। जब जिला अटॉर्नी का नोट खंड विकास और पंचायत अधिकारी के समक्ष रखा गया, तो उन्होंने 26 जनवरी, 1970 को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के संबंधित फैसले उनके सामने रखे जाएं। इसके बाद मामले को 29 जनवरी को संबंधित फैसलों की प्रतियों के साथ उनके समक्ष वापस रखा गया। 28 फरवरी, 1970 को, खंड विकास और पंचायत अधिकारी ने मामले पर एक नोट दर्ज किया जिसमें उन्होंने सिफारिश की; (क) चूंकि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत पहले ही दर्ज किया जा चुका है और उस पर कार्यवाही की जा रही है, इसलिए विभाग को इसे वापस नहीं लेना चाहिए बल्कि इस पर निर्णय लेने का कार्य न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए; और- (ख) याचिकाकर्ता के निलंबन का पूर्व आदेश सरकार द्वारा किसी भी जांच के दौरान अन्यथा पारित किया गया था, निलंबन का आदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत था और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता को सरपंच के रूप में ड्यूटी पर वापस रखना उचित नहीं होगा और यह उसके द्वारा सुझाया गया था, बहाली के तुरंत बाद, सरकार द्वारा जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को जांच के दौरान फिर से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो, तो सरकारी अधिवक्ता से इस संबंध में परामर्श किया जा सकता है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का उपरोक्त नोट जब उपायुक्त के पास पहुंचा

तो उन्होंने इस आशय के आदेश पारित किए कि वे आपराधिक मामला वापस न लेने के संबंध में पहले सुझाव से सहमत हैं, लेकिन वह निलंबन के आदेश की वैधता के संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं थे और उन्होंने सोचा कि याचिकाकर्ता का निलंबन क्रम में है। 20 अप्रैल, 1970 को, हालांकि, उपायुक्त ने जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ इस मामले पर चर्चा की - उन्हें दिखाए गए उच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों के मद्देनजर और मामले और उच्च न्यायालय के फैसलों पर पुनर्विचार करने पर, उन्होंने 2 मार्च, 1970 के अपने पहले के फैसले की समीक्षा की, दूसरे बिंदु पर और 28 फरवरी को खंड विकास और पंचायत अधिकारी के सुझाव (बी) को मंजूरी दी। 1970, याचिकाकर्ता की बहाली और उसके निलंबन के बारे में। उपायुक्त के आदेश को तब जिला विकास और पंचायत अधिकारी और जिला अटॉर्नी को भेजा गया था। जिला अटॉर्नी गुरप्रसाद ने 8 मई, 1970 को अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की और उसके बाद 17 मई, 1970 को अनुमोदन के लिए मसौदा जिला विकास और पंचायत अधिकारी के समक्ष रखा गया। मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद, याचिकाकर्ता को बहाल करने का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद जांच का आदेश दिया गया जिसके दौरान याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। मामले का इतिहास, जैसा कि ऊपर संदर्भित मूल आधिकारिक रिकॉर्ड से उभरता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तव में याचिकाकर्ता को किसी भी समय किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त नहीं किया गया था। यह आगे दर्शाता है कि मूल कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र और निलंबन का आदेश सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था क्योंकि वे इस न्यायालय की घोषणाओं के अनुसार अमान्य पाए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील नरूला ने कहा कि बहाली का आदेश जो किसी भी कारण से समर्थित नहीं है, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ तय किए गए आरोपों से मुक्त करने के समान है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। बहाली का आदेश केवल निलंबन के पिछले आदेश को समाप्त करने के समान था। जिन परिस्थितियों में यह हुआ, वे आधिकारिक रिकॉर्ड से अधिक स्पष्ट हैं जो इस मामले में जारी नियम की वापसी के समर्थन में पेश किए गए थे। अपनी पहली दलील के संबंध में श्री नरूला द्वारा तर्क दिया गया एकमात्र अन्य बिंदु यह है कि आपराधिक (भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत कार्यवाही) के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 102 के तहत कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मेरी राय में, यह निवेदन समान रूप से किसी भी बल से रहित है। अधिनियम की धारा 102 (2) के तहत सरपंच के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी जांच के दौरान धारा 102 की उप-धारा (1) के तहत उसे

निलंबित करने पर कोई रोक नहीं थी, भले ही उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही कानून की सक्षम अदालत में लंबित हो।

5. यह मुझे श्री नरूला द्वारा उठाए गए दो शुद्ध रूप से वैध प्रश्नों की ओर ले जाता है। अधिनियम की धारा 102 इस प्रकार है:-

"102(1) उपायुक्त, जांच के दौरान, किसी पंच को किसी भी कारण से निलंबित कर सकता है, जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है और उसे उस अवधि के दौरान उक्त निकाय के किसी भी कार्य और कार्यवाही में भाग लेने से रोक सकता है और उसे उक्त निकाय के रिकॉर्ड, धन, या किसी भी संपत्ति को इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति को सौंपने का आदेश दे सकता है।

2. सरकार, ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझे, किसी भी पंच को हटा सकती है-

a. धारा 6 की उप-धारा (5) में उल्लिखित किसी भी आधार पर।

b. जो कार्य करने से इनकार करता है, या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;

c. जो उचित कारण के बिना, ग्राम पंचायत या अदालत पंचायत की बैठकों से लगातार दो महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, जैसा भी मामला हो;

d. जो सरकार की राय में या उस अधिकारी की राय में, जिसे सरकार ने हटाने की अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है, कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी रहा है;

e. जिसका पद पर बने रहना, सरकार की राय में या उस अधिकारी की राय में, जिसे सरकार ने हटाने की अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, जनता के हित में अवांछनीय है:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात सरकार को किसी पंच को हटाने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी खंड (घ) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उन कृत्यों के लिए जो उसके ठीक पहले उसके पदावधि के दौरान किए गए या छोड़े जाने के लिए किए गए हैं, जिसमें हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है:

बशर्ते कि सरकार इस उप-धारा के तहत पंच को हटाने की अधिसूचना जारी करे, प्रस्तावित निष्कासन के कारणों के बारे में संबंधित पंच को सूचित किया जाएगा और उसे लिखित में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण खंड (घ) में 'कदाचार' शब्द में पर्याप्त कारण के बिना सरपंच की विफलता शामिल है-

(i) ऐसा करने के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर

किसी मामले की न्यायिक फाइल प्रस्तुत करना;

(ii) किसी प्रशासनिक या न्यायिक मामले में ग्राम पंचायत के आदेश की एक प्रति उसके द्वारा तय किए गए उसके लिए वैध आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर प्रदान करना।

3. उपधारा (2) के तहत हटाए गए व्यक्ति को पांच साल से अधिक की अवधि के लिए फिर से चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसा कि सरकार तय कर सकती है।

श्री नरूला का तर्क यह है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को अधिनियम की धारा 102 (1) के तहत सरपंच के निलंबन के समय सरपंच के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है जो सरपंच के रूप में निर्वाचित नहीं हुआ है और ऐसा होने पर, किसी भी सरपंच को निलंबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पंचायत सरपंच के बिना कार्य करना बंद कर देगी और ऐसी स्थिति पैदा करना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा, 10 में सरपंच की रिक्ति को केवल उसमें उल्लिखित तीन आकस्मिकताओं में भरने का प्रावधान है, अर्थात, रिक्ति के मामले में (i) मृत्यु से, (ii) इस्तीफे से, या (iii) सरपंच को हटाकर और किसी अन्य आकस्मिकता में नहीं। अधिनियम की धारा 10 इस प्रकार है:-

"10. जब भी किसी पंच या सरपंच की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने से कोई रिक्ति होती है, तो एक नया पंच या सरपंच, जैसा भी मामला हो, ऐसी रीति से चुना जाएगा जो निर्धारित किया जाए, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उस कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा, जिस समय लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह चुना गया था, अन्यथा पद पर बना रहता ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 10 में सरपंच के निलंबन से सृजित रिक्ति का प्रावधान नहीं है। न ही धारा 10 धारा 102 के तहत निलंबित सरपंच के स्थान पर एक नए सरपंच के चुनाव को अधिकृत करती है। लेकिन अधिनियम की धारा 25 में निम्नानुसार प्रावधान है -

"15(1) सरपंच और, उसकी अनुपस्थिति में, पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुना गया पंच, सभा या पंचायत से संबंधित या निहित सभी निर्धारित रिकॉर्ड और रजिस्टरों और अन्य संपत्ति के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा और, अपने कार्यालय को छोड़ने पर, निवर्तमान सरपंच या पंच उन्हें सरपंच या ऐसे अन्य पंच को सौंप देगा जो उपायुक्त द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जाए।

2. यदि पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर,

ऐसी मांग के दस दिनों की अवधि के भीतर कोई व्यक्ति उप-धारा (I) के तहत निर्धारित रिकॉर्ड और रजिस्टर और सभा या पंचायत से संबंधित या निहित अन्य संपत्ति को उस उप-धारा में निर्दिष्ट सरपंच या पंच को सौंपने में विफल रहता है, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में सभा क्षेत्र स्थित है, ऐसे व्यक्ति से अभिलेख, रजिस्टर और अन्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए।

* * * « * * *

मेरी राय में, यह सरकार के लिए खुला है कि वह पंचायत को सरपंच के रूप में कार्य करने के लिए अपने मौजूदा पंचों में से एक का चुनाव करने के लिए कहे एक सरपंच की अनुपस्थिति के दौरान सभी निर्धारित रिकॉर्ड और रजिस्टर आदि के रखरखाव के लिए, जिसे निलंबित किया गया हो । ऐसा होने पर, ऐसा कोई गतिरोध पैदा होने की संभावना नहीं है जैसा कि श्री नरूला ने जांच लंबित रहने तक एक सरपंच के निलंबन से आशंका जताई है। उत्तर *प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (1947 का 26) की धारा 95* में सर्वोच न्यायालय के लॉर्डशिप के हालिया फैसले ***सब-डिवीजनल 'ऑफिसर, सरदार, फैजाबाद* बनाम *शंभू नारायण सिंह*** [1]से वकील ने अपनी दलील की ताकत हासिल की है, जिसमें उन दंडों का उल्लेख किया गया है जो एक ग्राम सभा के निर्वाचित प्रधान को दी जा सकती हैं। उस अधिनियम की धारा 95 (जी) में उल्लिखित दंडों में से एक प्रधान के निलंबन का है। इस शक्ति का कथित इस्तेमाल करते हुए ग्राम सभा, आसापुर के शंभू नारायण सिंह को 18 सितंबर, 1963 को सदर फैजाबाद के अनुविभागीय अधिकारी ने निलंबित कर दिया था। उस आदेश की वैधता को एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, लेकिन उस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अपील पर इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि धारा 95 (1) (जी) उप-विभागीय अधिकारी को आक्षेपित आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देती है। डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता को सर्वोच न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया था। सरकार और प्रधान उप-मंडल अधिकारी के बीच इस आशय का तर्क कि एक स्वामी और नौकर का संबंध बनाया गया था, सरकार के पास प्रधान के खिलाफ जांच के दौरान उसे निलंबित करने की अंतर्निहित शक्ति थी, सर्वोच न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एक प्रधान को सरकार का सेवक नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि है और कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। उसके और सरकार के बीच मालिक

[1] A.I.R 1970 S.C.1940

और नौकर का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश अधिनियम में जांच लंबित रहने तक प्रधान के निलंबन को अधिकृत करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। निलंबन केवल सजा में से एक के रूप में प्रदान किया गया था। सर्वोच न्यायालय ने कहा कि इसलिए सरकार के पास प्रधान को निलंबित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। निलंबन की शक्ति को हटाने के आदेश के निष्पादन के एक अनिवार्य भाग के रूप में निहित होने के बारे में उप-विभागीय अधिकारी की ओर से संबोधित तर्क को सर्वोच न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ऐसी शक्ति केवल तभी निहित की जा सकती है जब यह प्रदान की गई शक्ति के निर्वहन के लिए बिल्कुल आवश्यक हो, न कि केवल इसलिए कि ऐसी शक्ति होना सुविधाजनक है। सर्वोच न्यायालय का फैसला तैयार करने वाले हेज,न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 95 (एल) (जी) के तहत प्रदत्त शक्ति के उचित प्रयोग के लिए किसी अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति अत्यंत आवश्यक है। जांच के दौरान हस्तक्षेप की केवल संभावना या शक्तियों के और दुरुपयोग की संभावना को वैधानिक शक्ति के दायरे को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) विशेष रूप से उपायुक्त को सरकार द्वारा आदेशित जांच के दौरान एक सरपंच को निलंबित करने के लिए अधिकृत करती है। उत्तर प्रदेश अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया। हेज, जे ने विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस संबंध में टिप्पणी की, जैसा कि नीचे दिया गया है: –

> "हमारा ध्यान न तो अधिनियम में और न ही इसके तहत बनाए गए नियमों में किसी प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता (उप-विभागीय अधिकारी) इस तरह का आदेश (जांच के दौरान प्रधान को निलंबित करने का आदेश) कर सकता था।
>
> सर्वोच न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया कि पी.पी. अधिनियम में पंजाब अधिनियम (हरियाणा में लागू) की धारा 15 की तरह कोई प्रावधान नहीं है, जो निर्वाचित की अनुपस्थिति के दौरान सरपंच के चुनाव या नियुक्ति को अधिकृत करता है।

6. यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि अधिनियम की धारा 10 में जांच लंबित निलंबन के मामले में कोई लागू नहीं है। श्री नरूला ने हालांकि दलील दी कि इस मामले में धारा 15 भी लागू नहीं हो सकती। उनका कहना था कि सरपंच के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति

उसके निलंबन के कारण होती है और चूंकि अधिनियम की धारा 10 में इस तरह की रिक्ति के लिए किसी अन्य सरपंच को चुने जाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए धारा 15 की भाषा को उस अंतर को भरने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसे विधायिका द्वारा जानबूझकर छोड़ दिया गया है। मैं श्री नरूला के इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। धारा 15 उन व्यवस्थाओं से संबंधित सामान्य प्रावधान है जो सरपंच की अनुपस्थिति के दौरान की जा सकती हैं। आम तौर पर प्रावधान अस्थायी और साथ ही आकस्मिक प्रकृति की स्थायी रिक्तियों को कवर करता, लेकिन धारा 10 को आकस्मिक प्रकृति की रिक्तियों के मामलों को कवर करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में लागू किया गया है जो इस अर्थ में स्थायी हैं कि सीट खाली करने वाला सरपंच संभवतः अपने कार्यालय के शेष कार्यकाल के दौरान इसमें वापस नहीं आ सकता है। धारा 15 अन्य सभी मामलों पर लागू होती है। जबकि एक नए सरपंच को धारा 10 के तहत चुना जाना है, एक मौजूदा पंच को अकेले एक सरपंच के निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है जो धारा 15 के तहत अनुपस्थित है। फिर, धारा 10 के तहत एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सरपंच मूल सरपंच के शेष कार्यकाल के दौरान तक पद पर रहता है, लेकिन धारा 15 के तहत सरपंच के निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चुना गया पंच केवल तब तक काम करता है जब तक कि मूल सरपंच वापस नहीं आ जाता या अपना कार्यालय खाली नहीं कर देता और धारा 10 के तहत एक नव निर्वाचित सरपंच द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नव निर्वाचित सरपंच के पास सरपंच की सभी शक्तियां हैं, लेकिन धारा 15 के तहत निर्वाचित एक व्यक्ति केवल उस प्रावधान में उल्लिखित कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इसलिए, दो खंड विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए हैं। मेरी राय में, धारा 15 संबंधित पंचायत के मौजूदा पंचों में से किसी को भी सरपंच के रूप में निर्वाचित करने के लिए अधिकृत करती है, जो मूल सरपंच की अनुपस्थिति के दौरान उस कार्यालय के निर्दिष्ट कार्यों को पूरा कर सकता है, जिसे जांच के दौरान निलंबित किया गया है। उपायुक्त ने इस मामले में किसी को नियुक्त नहीं किया है। खंड विकास और पंचायत अधिकारी को निर्देश कानून के अनुसार है और यह माना जाता है कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की समाप्ति तक अधिनियम की धारा 15 के तहत सरपंच के कार्यों को पूरा करने के लिए पंचायत को अपने पंचों में से एक का चुनाव करने की आवश्यकता होगी। मामले के इस दृष्टिकोण में, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई जाती है। मेरा मानना है कि धारा 102 (1) *अंतर्अधिकार है,* कि पंचायत जांच के दौरान सरपंच के निलंबन की अवधि के दौरान सरपंच के निर्दिष्ट कार्यों

को करने के लिए अपने पंचों में से एक का चुनाव कर सकती है और याचिकाकर्ता के निलंबन का आक्षेपित आदेश वैध और कानून के अनुसार है। इसलिए, यह याचिका विफल हो जाती है और लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी